

इसके अलावा संतों एवं जारियों के लिए फार्मर आईडी और ई-टोकन प्रणाली लागू करने की मांग भी रखी गई, ताकि उन्हें बाढ़, बीज और कृषि से जुड़ी अन्य सुविधाएं किसानों की तरह आसानी से मिल सकें।